मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

मानेसर के संघर्षरत मज़दूरों के समर्थन में, ज़ोरदार प्रदर्शन 2
संभावित शिकारों को फंसाएंगे, अम्मा की आय बढ़ाएंगे 4
ज्योति मौर्य के किस्से का सच या झूठ 5
पंडित जवाहरलाल नेहरू : वैज्ञानिक मानसिकता के धनी 6
डीईओ को फरीदाबाद का अतिरिक्त चार्ज देकर मुनेश के लिए पद खाली रखा 8

वर्ष 37 | अंक -50 | फरीदाबाद | 16 जुलाई-22 जुलाई 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

डीजीपी बनने की रेस में तीन आगे

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद। तीस जून को रिटायर होने वाले डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को 15 अगस्त तक का विस्तार दे दिया गया था। इस बीच हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार नौ अफसरों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है। ये तमाम अधिकारी डीजीपी रैंक में होने के साथ-साथ तीस साल का सेवाकाल होने की शर्त भी पूरी करते हैं। इन नौ में से किन्ही तीन का पैनल बनाकर यूपीएससी हरियाणा सरकार को भेजेगी जिनमें से किसी एक को हरियाणा पुलिस पद पर तैनात किया जाएगा।

पैनल में भेजे गए नामों में सबसे ऊपर 1989 बैच मो. अकील, दूसरे नंबर इसी बैच के आरसी मिश्रा तथा तीसरे नंबर पर 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर हैं। इन तीनों में से भी वरिष्ठ हरियाणा काडर के 1988 बैच के मनोज यादव हैं जो यहां पर दो साल डीजीपी रहकर जा चुके हैं। उनका नाम इस पैनल में नहीं भेजा गया है, कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने इस पद पर आने से इनकार कर दिया। हालांकि, नियमानुसार तो उनका नाम भेजा ही जाना चाहिए था।

यदि मनोज यादव का नाम भी भेजा गया होता तो दस अफसरों के उस पैनल में शत्रुजीत कपूर का नंबर चौथा हो जाता।

यूपीएससी केवल तीन नामों का पैनल भेजती है, ऊपर के तीन नामों में से किसी एक को काटने के लिए यूपीएससी को उचित कारण बताने होते हैं। इसके बिना इनमें से किसी का भी नाम काटा नहीं जा सकता। जानकारों के मुताबिक मनोज से लेकर शत्रुजीत कपूर तक किसी के भी नाम को काटे जाने के कोई भी कारण यूपीएससी के पास उपलब्ध नहीं हो सकते, जाहिर है ऐसे में यूपीएससी को जिन तीन का नाम भेजना पड़ता उनमें मनोज यादव नंबर एक पर होते। इसलिए उनका नाम न भेज कर शत्रुजीत कपूर का रास्ता खोल दिया गया।

सर्वविदित है कि अपने डीजीपी कार्यकाल के दौरान मनोज यादव तथा गृहमंत्री अनिल विज के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा। विज को वे फूटी आंख नहीं सुहाते थे बल्कि उन्हीं के दबाव में यादव को यहां से जाना पड़ा था। फिलहाल वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तैनात हैं। वैसे तो वे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो (डीआईबी)पद के प्रबल दावेदार थे लेकिन किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उनसे नाराज हो गए थे।

ये तो तय है कि यूपीएससी से ऊपर के ही तीन नामों का पैनल आने वाला है, अब इनमें से किसके सिर पर ताज सजेगा इसे हरियाणा सरकार तय करेगी। ये तीनों ही अधिकारी हर तरह से उपयुक्त माने जाते हैं।

मो. अकील के लिए उनका मुस्लिम चेहरा होना ये दिखाने के लिए बेहतरीन हो सकता है कि भाजपा सरकार ने उस अल्पसंख्यक वर्ग के एक अफसर को अपना पुलिस प्रमुख बनाया है जिनकी आजकल उपेक्षा का आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है। इसी आरोप को लेकर न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की अच्छी खासी फजीहत हो रही है। मो. अकील काम के जानकार व कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ-साथ सरकार के सभी वर्गों को संतुलित करके चलने में महारत रखते हैं।

नंबर दो पर आने वाले आरसी मिश्रा पर न केवल पूर्व मंत्री राम बिलास शर्मा की मुहर लगी हुई है बल्कि वे आरएसएस से भी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसी घनिष्ठता के चलते उनकी पत्नी के डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल होते हुए भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर नियुक्ति हो चुकी है। जबकि, कॉलेज का प्रोफेसर या प्रिंसिपल होना वाइस चांसलर पद पर नियुक्त होने की योग्यता नहीं माना जा सकता।

ऐसे में समझा जा सकता है कि आरएसएस लॉबी तथा अनिल विज उनके लिए अपना पूरा जोर लगा सकते हैं। यहां विज के लिए जोर लगाना इसलिए भी जरूरी है कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि तीसरे नंबर के उम्मीदवार कपूर इस पद पर आसीन हो सकें। सर्वविदित है कि इन दोनों का भी हमेशा का छत्तीस का आंकड़ा रहा है।

मनोज यादव का नाम हटा कर कपूर को तीसरे नंबर पर रखने के पीछे मुख्यमंत्री खट्टर की चाल भी समझा जा रहा है। कपूर शुरू से ही खट्टर के विश्वसनीय एवं चहेते रहे हैं। यूं भी कपूर हर लिहाज से अपने काम में माहिर हैं, उनकी पेशेवराना योग्यता में कभी कोई कमी देखने को नहीं मिली है। लेकिन उनके रास्ते में विज के अलावा दूसरी बड़ी रुकावट राज्य की आईएएस लॉबी है।

सर्वविदित है कि पिछले दिनों भ्रष्टाचार में लिप्त अनेकों आईएएस अफसरों को इन्होंने अच्छे से लपेटा लगाया था जिसे लेकर न केवल आईएएस लॉबी में बल्कि पूरी सरकार में हड़कंप मचा रहा। यह तो कानूनी बाध्यता है कि विजिलेंस के डायरेक्टर को मुख्य सचिव की सहमति लेना अनिवार्य होता है, इसलिए कपूर को कई बार ढील देनी पड़ी। जबकि डीजीपी पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती, उसे अपना काम स्वतंत्र रूप से करने की पूरी छूट होती है। यदि कहीं वे डीजीपी बन गए तो अन्य भ्रष्टाचारियों की तरह भ्रष्ट आईएएस अफसरों की भी मुसीबत तय है।

मौजूदा हालात एवं रस्साकशी के दौरान कोई पेशीनगोई करना तो उचित नहीं होगा लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को अपना राज्य चलाना है तो उसे डीजीपी तो अपनी पसंद का रखना ही होगा। यदि विज की पसंद का डीजीपी आ गया तो खट्टर के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे में बिल्ली के भागों छींका अकील के हक में भी टूट सकता है।

पहले बनाई सड़क, अब सीवर डालने के लिए उसे खोदेंगे

बड़खल विधानसभा क्षेत्र में 160 करोड़ रुपये खर्च कर, डाली जाएगी सीवर लाइन

फ़रीदाबाद (मजदूर मोर्चा) बड़खल विधानसभा में चंद सालों पहले बनाई गई आरएमसी सड़कें अब सीवर लाइन डालने के लिए खोदी जाएंगी। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई इन सड़कों पर सीवर लाइन डालने के बाद दोबारा बनाने पर फिर से करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। ये सब नगर निगम में बैठे फर्जी डिग्री वाले इंजीनियर और अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली का नतीजा है।

बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एनआईटी एक, दो, तीन, पांच, एसजीएम नगर आदि इलाकों में सीवर चोक और जलभराव की समस्या के मद्देनजर 2015 में यहां नई सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। निगम के भ्रष्ट अधिकारी और फर्जी डिग्री वाले इंजीनियर इन इलाकों में सीवर लाइन डालने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार नहीं कर सके। अभी सीवर लाइन पड़ी भी नहीं थी कि 2016-17 में एनआईटी एक, दो, तीन, पांच और एसजीएम नगर क्षेत्र सहित बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आरएमसी सड़कें बिछाई जाने लगीं। उस समय पार्षदों ने आरएमसी सड़कों के नीचे दब गई सीवर लाइनों की सफाई का मामला उठाया था लेकिन विधायक सीमा त्रिखा के आगे किसी की नहीं चली और सड़कें बना दी गईं।

निगम के फर्जी इंजीनियरों ने आरएमसी सड़कों का तो जाल बिछा दिया लेकिन इनके साथ कहीं भी नालियां नहीं बनाई गईं। अभी तक तो सिर्फ सीवर जाम की समस्या थी अब नालियां खत्म होने से जलभराव की समस्या भी होने लगी। रही सही कसर भ्रष्ट अधिकारियों ने नाला सफाई के नाम पर लाखों रुपये की बंदरबांट कर पूरी कर दी। ड्रेनेज

व्यवस्था समाप्त होने के कारण पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बनने लगी।

अब चुनावी वर्ष शुरू हुआ तो विधायक सीमा त्रिखा को अपने विधानसभा क्षेत्र की सीवरेज समस्या का ध्यान आया। कई साल से लटके प्रोजेक्ट को बरसात समाप्त होने के बाद शुरू करने की तैयारी हो रही है। यानी नई सीवर लाइन डालने के लिए एक बार फिर सड़कों को खोदा जाएगा। सड़कों की खुदाई के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद किए जाएंगे और सीवर लाइन डाले जाने के बाद इनकी मरम्मत के नाम पर फिर से करोड़ों रुपये खर्च। अधिकारी भी यही चाहते हैं कि इस तरह की तोड़ फोड़ होती रहे और उनकी जेबें भरती रहें।

बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश गोयल कहते हैं कि भ्रष्ट निगम अधिकारियों के कारण एनआईटी की टाउनशिप प्लानिंग ध्वस्त हो गई। हर इमारत में पर्याप्त धूप-हवा उपलब्ध हो इसके मद्देनजर हरियाली और खुली हुई जगह के बीच प्लॉटिंग की गई थी।

भ्रष्ट अधिकारियों ने चंद पैसों के लालच में बिल्डरों से गठजोड़ कर एफएआर, सबडिवीजन आदि नियमों को ताक पर रख कर अवैध निर्माण कराए। चार पांच गुना आबादी बढ़ने से सीवर लाइन ओवरलोड हुईं तो इन्हें सुधारने के बजाय ड्रेनेज सिस्टम भी खत्म कर दिया। बरसाती पानी की निकासी का बोझ भी इन पर डाल दिया गया।

उनका मानना है कि यदि पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम सही कर लिया जाए और अधिकारी हर साल नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये डकारने की जगह गंभीरता से नालों की सफाई करवाएं तो बरसात में जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी और सीवरलाइन पर बेवजह का बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा करने पर बार बार तोड़ फोड़ और निर्माण कराने में जो कमीशन बनता है वो मिलना बंद हो जाएगा।